



स्वामित्व

(गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण)



मेरी सम्पत्ति मेरा हक

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	02
सुधार की आवश्यकता	03
व्यापक उद्देश्य	04
स्वामित्व योजना में विभिन्न चरणों की झलक	05
संपत्ति कार्ड के नमूने	06
स्वामित्व में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है - सी.ओ.आर.एस, ड्रोन, डिजी-लॉकर और डैशबोर्ड	08
कवरेज	12
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ	14
संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण परिदृश्य के लिए लाभ	15
सफलता की कहानियां	18
ग्रामीण भूमि और संपत्ति: स्वामित्व से पहले और बाद में	22
संपत्ति कार्ड वितरण	23
समर्थन	25

“

भूमि और घरों का स्वामित्व देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब परिसम्पत्ति रिकॉर्ड होता है, तो नागरिकों का विश्वास बढ़ता है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी



प्रस्तावना

स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से गांव का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण) की ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आबादी परिसम्पत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के पायलट चरण का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को किया गया।

ग्रामीण आबादी भूमि का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), राज्य राजस्व विभागों और राज्य पंचायती राज विभागों के सहयोगात्मक प्रयासों से ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया जाता है। यह परिसम्पत्ति कार्डों/ हक विलेखों के रूप में गांव के गृह स्वामियों को “अधिकारों का रिकार्ड” प्रदान करेगा।

सुधार की आवश्यकता

स्वतंत्रता के बाद से, ग्रामीण भूमि के सरकारी सर्वेक्षण कृषि भूमि तक ही सीमित रहे हैं। कई राज्यों में गांवों के बसे हुए क्षेत्र - जिन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में “आबादी” भूमि के रूप में जाना जाता है, पंजाब और हरियाणा में “लाल डोरा” भूमि, महाराष्ट्र और गुजरात में “गौठान” भूमि के रूप में जाना जाता है - बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों के दायरे से बाहर रह गए हैं।

जिसके परिणाम स्वरूप, भारत में कई ग्रामीण समुदायों के पास अधिकारों का रिकॉर्ड नहीं है, और “आबादी” क्षेत्र में भूमि पर स्वामित्व का उनका दावा काफी हद तक संपत्ति के वास्तविक कब्जे पर निर्भर करता है। एक कानूनी दस्तावेज के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, राज्य भू-राजस्व संहिता/अधिनियमों में संशोधन द्वारा समर्थित घर के मालिक को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए, ग्रामीण परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है।

व्यापक उद्देश्य



सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर कुशल ग्रामीण नियोजन को सक्षम बनाना



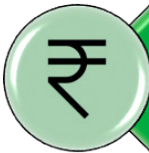
गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने में लोगों की सहायता करना



बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान करना



संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने में मदद



ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर का निर्धारण



मानचित्रण और स्थानीय सेवाओं के लिए स्टेशनों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना

स्वामित्व योजना में विभिन्न चरणों की झलक



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



सी.ओ.आर.एस स्टेशन सेटअप



ग्राम सभा का आयोजन



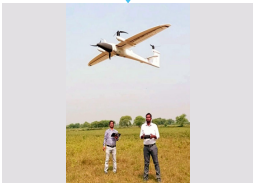
निश्चित बिंदुओं की स्थापना



जमीन पर अंकन



आई. ई. सी. - वॉल पेंटिंग



ड्रोन सर्वेक्षण



फ़ीचर निष्कर्षण



मानचित्रों का निर्माण

आयुक्तिक विकास विभाग राजस्थान सरकार		Panchayat Raj राजस्थान सरकार	
प्लॉट नंबर	प्लॉट का नाम	प्लॉट नंबर	प्लॉट का नाम
प्लॉट का क्षेत्रफल	प्लॉट का कर्णा	प्लॉट का क्षेत्रफल	प्लॉट का कर्णा
प्लॉट का स्थान	प्लॉट का स्थान	प्लॉट का स्थान	प्लॉट का स्थान
प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक
प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक
प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक
प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक
प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक
प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक
प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक	प्लॉट का मालिक

अंतिम संपत्ति कार्ड का नमूना उत्पन्न



विवाद समाधान



Government of Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश सरकार
Corridor of Rural Habitation-Gharuani (ROH)
ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घराने)



Department of Revenue
(राजस्व विभाग)

Department of Panchayati Raj
(पंचायती राज विभाग)

District (जिला)	Tahsil (तहसील)	Block (ब्लॉक)	Gram Panchayat (ग्राम पंचायत)	Police Station (थाना)	Village Code : Name (ग्राम कोड : नाम)	Survey Year (सर्वेक्षण वर्ष)	Document No (अभिलेख सं)	
बाराबंकी	नवावागंज	देवा	मुसदाबाद	देवा	नरगिसमऊ : 164577	2020		
1. Aabadi Gata Number (आबादी गाटा संख्या)	2. Plot No (प्लॉट संख्या)	3. Property Unique ID No (प्लॉट संख्या युनिक आईडी नं)	4. Property Classification (संपत्ति वर्गीकरण)	5. Area of property (in sq.m.) (प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में))	6. Dimensions (in m) (आयाम (मीटर में))	7. Property Sketch (नक्शा)		
			4.1 Type (श्रेणी)	4.2 Sub Type (उप श्रेणी)	No of Sides (प्लॉटों की संख्या)	Lengths of Sides (प्लॉटों की लंबाई)		
133	67		निजी व्यक्तिगत पारिवारिक भवन एवं भूमियां-श्रेणी-6	पक्का मकान	161.23	4	4.23,31.7,31.22,4.61	
8. Bounded by -East (पूर्व चोहदी)		9. Bounded by -West (पश्चिम चोहदी)		10. Bounded by -North (उत्तर चोहदी)		11. Bounded by -South (दक्षिण चोहदी)		
सड़क		बुन्दे लाल		रमेषा		रास्ता		
12. Owners' Names (भू-स्वामियों के नाम)			13. Father/Mother/Husband/Wife Name (पिता / माता / पति / पत्नी का नाम)		14. Address of Owner (भू-स्वामी का पता)		15. Share of Owner (भू-स्वामी का हिस्सा)	
रामू			बृज लाल		नि: ग्राम		1/3	
17. Remark (अभियुक्ति)			-					16. GP Resolution No. and Date (ग्राम पंचायत संख्या एवं तिथि)
								1/2020 : 2020-09-01 00:00:00
Assistant Record Officer (सहायक अभिलेख अधिकारी)								
18. Printed Date (मुद्रित तिथि)		19. Printing id (मुद्रित आईडी)		20. Service Change (सेवा करने का प्रकार)		21. Place of Issue (जारी करने का स्थान)		
						22. QR Code (क्यूआर कोड)		
						Digital Signature (डिजिटल सिग्नेचर)		

उत्तर प्रदेश

अधिकार अभिलेख

प्ररूप- तीन
(नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता(भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम,2020

ग्राम/नगर.. देवरी कला.. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक... 49..तहसील...शहपुरा...जिला.. डिंडोरी

संरल क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/दस्ता संख्यांक	भू-खण्ड संख्यांक (दस्ता संख्यांक में)	पूर्वतन सर्वेक्षण संख्यांक	1. क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है।	1. भूमिस्वामी / सरकारी पट्टेदार का नाम	अधिकार की प्रकृति	संयुक्त खाल की दशा में प्रत्येक खालेदार के हित की सीमा पता	1. अधिभोगी कृषक का नाम (यदि कोई हो)	भूमि पर विलग्न तथा प्रभार	अभ्युक्ति या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	278	4		209	आवासीय	फूलचंद पिता लालसाय विरसंजन पिता लालसाय	भूमि स्वामी	%			
								%			

मध्य प्रदेश

स्वामित्व में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना- सी.ओ.आर.एस और ड्रोन

उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्र बनाने के लिए सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (सी.ओ.आर.एस.) नेटवर्क के साथ सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियां भूखंडों के आयामों की आसान पहचान को सक्षम करती हैं।

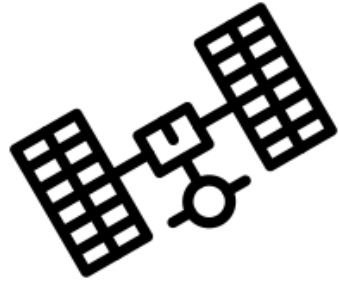
पूरे देश को कवर करने के लिए लगभग 2000 कुशल जनशक्ति को नियोजित करने वाली कुल 500-600 ड्रोन टीमों।



उच्च गुणवत्ता सर्वेक्षण ग्रेड यूएवी/
ड्रोन 1:500 के पैमाने पर +/-
5 सेमी की सटीकता के साथ
मानचित्र तैयार करने में सक्षम
बनाता है।



567 सीओआरएस स्टेशनों के
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का
निर्माण, यानी एक भू-स्थितिगत
बुनियादी ढांचा, जिसका उपयोग
कई राज्यों में प्रचलित श्रृंखला
सर्वेक्षणों को बदलने के लिए
किया जा सकता है।



इससे लोक निर्माण कार्यों के आकलन और जांच में सभी विभागों
को लाभ मिलेगा।

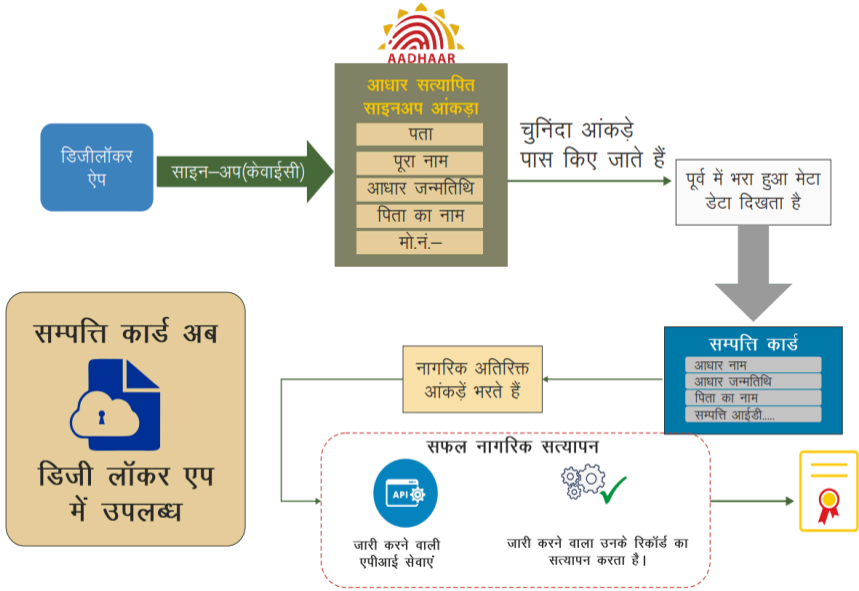
स्वामित्व में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना - डिजी-लॉकर और डैशबोर्ड

स्वामित्व डैशबोर्ड

ऑनलाइन निगरानी प्रणाली - स्वामित्व योजना की वास्तविक समय प्रगति निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड।



डिजिलॉकर ऐप

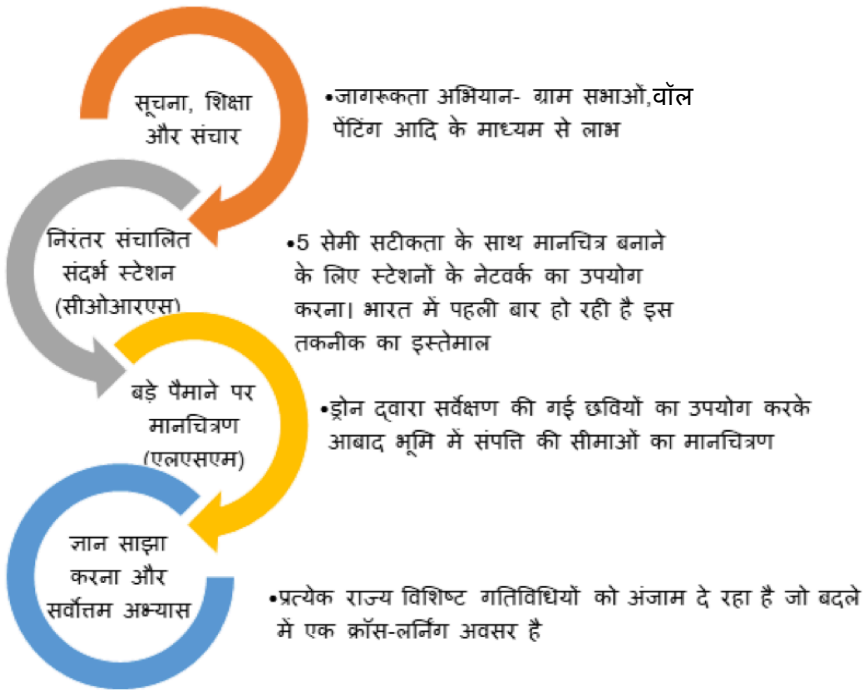


**प्रॉपर्टी कार्ड अब डिजिलॉकर ऐप में उपलब्ध हैं।
लाभार्थी अब डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से
संपत्ति कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।**

कवरेज

- नौ राज्यों में पायलट चरण - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
- चरणों में कार्यान्वयन - लगभग 6.62 लाख गांवों का कवरेज।
- 50,000 गांवों को अप्रैल 2020-मार्च 2021 तक और देश भर के शेष गांवों को 2021-25 तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना की व्यापक गतिविधिया



माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ

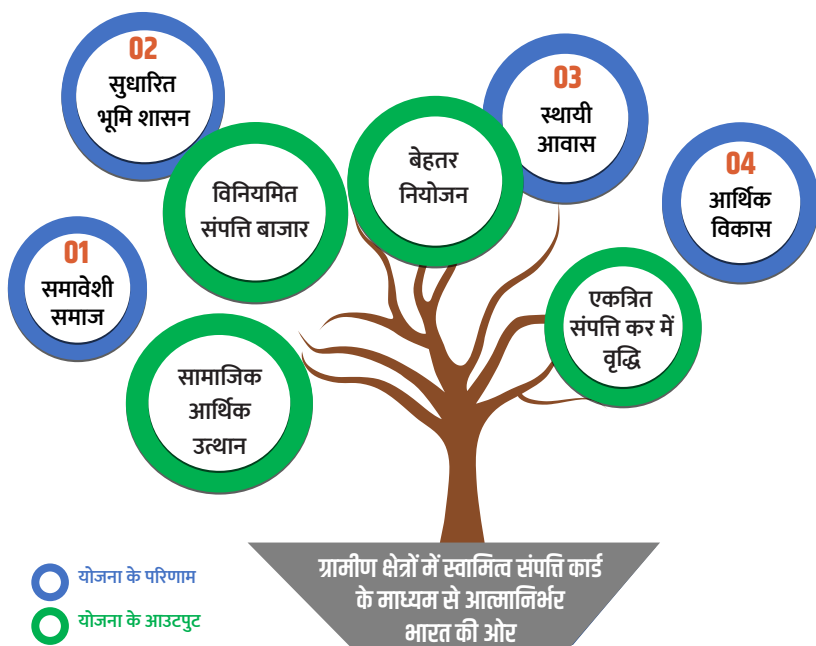


11 अक्टूबर 2020 को, योजना के पहले मील के पत्थर के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री ने छह पायलट चरण राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) के 763 गांवों के लगभग 1 लाख संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण की शुरुआत की।

संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण परिदृश्य के लिए लाभ

स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के निवासियों पर प्रत्यक्ष, दीर्घकालिक प्रभाव की कल्पना करती है।

प्रभाव के चार पहचाने गए व्यापक क्षेत्र



संपत्ति के मालिकों और ग्रामीण परिदृश्य के लिए स्वामित्व योजना के नेतृत्व में लाभ

समावेशी समाज



पूरे इतिहास में, विद्वानों और विकास विशेषज्ञों ने 'सम्पत्ति अधिकारों तक पहुंच' को 'गांवों में कमजोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक मानकों में सुधार' के साथ जोड़ा है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य उसी को सक्षम करना है।

भूमि शासन



दुनिया में भौतिक संपदा के निर्माण के उद्देश्य से किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है। स्पष्ट रूप से सीमांकित आबादी क्षेत्र की कमी के कारण भूमि-संघर्ष के मामलों की संख्या अधिक हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत और दुनिया भर में लाखों लोग भूमि संघर्षों के प्रभाव से पीड़ित हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल कारण का समाधान करना है।

स्थायी आवास



बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्रों का निर्माण, जिससे बुनियादी ढांचे जैसे स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नदियों, स्ट्रीट लाइट, सड़कों आदि में धन के कुशल आवंटन और पहुंच में वृद्धि के माध्यम से सुधार हो सके।

आर्थिक विकास



इस योजना का मुख्य परिणाम लोगों को अपनी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में मुद्रिकृत करने में मदद करना है। इसके अलावा, उन राज्यों में संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जहां यह लगाया जाता है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है और व्यापार करने में आसानी होती है।

सफलता की कहानियां

स्वामित्व योजना के तहत लिया गया ऋण

उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के नवाबगंज तहसील नवाबगंज के गांव मोहम्मदपुर चौकी में एक महिला गृहस्वामी **श्रीमती रामरती** ने अपने घर की मरम्मत और अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए एक हाथ गाड़ी की खरीद के लिए 20,000 रुपये का ऋण लिया है।



मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम अबगांवकला के श्री **रामभरोसे विश्वकर्मा** को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के खिलाफ स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के आधार पर **21.14 लाख रुपये का मुआवजा** मिला है।



उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गांवों की सफलता की कहानियां

पशुतैनी जमीन विवाद का निपटारा

श्री रामगोपाल, श्री चंद्रभान और श्री हरिश्चंद्र, ग्राम वाघेरा, तहसील, तहरोली के निवासी

उनकी पशुतैनी जमीन का विवाद कई सालों से लंबित था। पूर्व में विवादों को निपटाने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं रहे और पैतृक भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सका। स्वामीत्व संपत्ति कार्ड (घरौनी) के माध्यम से, भूमि का सीमांकन सफलतापूर्वक किया गया, जिससे उनके बीच लंबे समय से लंबित विवादों का निपटारा हुआ।

विवाद का निपटारा- अतिक्रमण हटाना

श्री सुवेन्द्र प्रकाश, निवासी ग्राम पाठा, तहसील गरौठा

श्री सुवेन्द्र के घर की ओर जाने वाले भूमि पार्सल पर अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके घर तक जाने के लिए केवल एक संकीर्ण मार्ग था, जिससे असुविधा हुई। स्वामीत्व योजना के माध्यम से अतिक्रमण को पहचानने और हटाने का प्रयास किया गया, जिससे मार्ग चौड़ा हो गया और मालिक के लिए आवाजाही में आसानी हुई।

स्वामित्व योजना के माध्यम से बैंक ऋण प्राप्त करना

श्री रामप्रकाश, निवासी ग्राम चित्तगुवन, मोठो तहसील

अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रामप्रकाश के पास कमाई के सीमित स्रोत हैं, जो उन्हें अपनी दुकान स्थापित करने से रोकता है। स्वामित्व योजना के तहत जारी संपत्ति कार्ड के आधार पर भूमि पार्सल नं। २५ गाँव में, श्री रामप्रकाश ने ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक से संपर्क किया, जिस पर बैंक ने सहमति व्यक्त की

उत्तराखण्ड के पौड़ी और हरिद्वार जिलों के गांवों की सफलता की कहानियां



हरिद्वार जिले के ग्राम नौकरीग्रांट के श्री तेजपाल और श्री धर्म सिंह के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों का निपटारा

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से लोगों को दी खसरा-खतौनी, ड्रोन कैमरे से प्रशासन की टीम कर रही है जीपीएस मैपिंग

140 लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला

भगवानपुर में स्वामित्व योजना के प्रमाण पत्र बांटे



भारत | हमारे संवाददाता



प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत में ग्रामीणों को आवासीय भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज़ बांटते विधायक।

लखनऊ तहसील के भगवानपुर गांव में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री को अंतर से किए गए विधायक और सरदारों ने तीन महीने के 140 लोगों को उनके आवास का मालिकाना हक दिलवाया। उन्हें खसरा खतौनी की नकल बांटी गई।

प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। इसमें नगर और देश में मूल आवस्यता से आवास नहीं पर मकान बनकर रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाना है। प्रधानमंत्री ने इसके तहत सर्वे कर रहा है। भगवानपुर में तहसीलाप्रधानमंत्री को अंतर के फैसलाकरण में मदद

कैप में सरकारी गांव के 56, पंचायतों के 40 व गांवों के 34 लोगों को उनके आवास की पूर्ण मालिकाना हक के दस्तावेज़ के लिए

खसरा खतौनी को नकल दी गई। भगवानपुर विधायक संजय गुप्ता और एसडीएम श्रीराम सिंह ने गांव में दौरा करके गांव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस योजना से गांवों में पूर्ण मालिकाना हक बांटेगा। अब वे जिस जमीन पर रह रहे

हैं, उनके बान्सी मालिक होंगे। इसके बाद वे सरकारी को आवासीय योजना व गांवों में निर्माण का अनुदान ले सकते हैं। साथ ही बैंक को उर्वर पर कर्तव्य के लिए बिना दस्तावेज़ के सकता है। एसडीएम ने बताया कि तहसील के

सभी गांवों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से जीपीएस मैपिंग की जा रही है। जमीनी कार्य जल्द मालिकाना हक के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इस बीच पर प्रशासन एजेंट मिटर, एटीओ पंचायत अलग फैसले, संभालना पंचायत राजपुर, अलग देव,

भगवानपुर | हमारे संवाददाता

कार्यक्रम

भगवानपुर तहसील ग्राम में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मन्ना रोकना ने किया। कार्यक्रम में भगवानपुर तहसील में 10 गांव के लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उन जिलेधारी मूल मालिकाना हक के प्रमाण पत्र बांटे। तहसीलाप्रधानमंत्री कुमार सेनी ने शुभारंभ कार्यक्रम में धारण स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया। भगवानपुर तहसील में 629 प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। एप्रैल 2020 के बीच पर 490 लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। जिसमें सितापुरी 90,

विद्यार्थी मन्ना रोकना ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। तहसील के दश गांवों के लोगों को प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र बांटे।
 खेराडी 84, बारपुर 4, बोटरी बुजुर्ग 47, कालाडी 50, हारपुर 17, लाल बाला मन्ना 74, मजिदपुर मन्ना बाला 38, बुधवार 30, ताताबाला खसरा 62, लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र बांटे। तहसीलाप्रधानमंत्री ने बताया कि भगवानपुर तहसील में स्वामित्व योजना का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही सभी गांव का कार्य पूरा कर लोगों को प्रमाण पत्र बांटे बांटे।

सुलत कुमार, इन्डिया विकास से अंतर लगे, टुंगलान, अंकि कुमार, देवरी विधान से प्रमाण कुमार के अंतर

सुलत, बनेराम, प्रदीप कुमार, सुधी मिश्र, राजेश कुमार, प्रधान प्रमाण कुमार अंकि कुमार।



स्वामित्व योजना का लाभ उठाकर जिला पौड़ी के गोदा गांव में संपत्ति मालिकों ने अपनी जमीन पर होम स्टे का निर्माण किया

पौड़ी जिला के गोदा ग्राम में होम स्टे का निर्माण पूर्ण



ग्रामीण भूमि और संपत्ति: स्वामित्व के पहले और बाद में

क्र. सं.	प्राथमिक उद्देश्य	स्वामित्व के पहले	स्वामित्व के बाद
1	बैंकों द्वारा ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण की मान्यता	अत्यधिक ब्याज दरों वाले साहूकारों पर निर्भरता	बैंक मानक प्रथाओं के अनुसार ऋण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं
2	सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे की सहायता करना	श्रमसाध्य जमीनी कार्य के आधार पर कार्यों की निगरानी	पंचायत व विभाग आसानी से अपने विकास की योजना बना सकते हैं
3	संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी के लिए प्रवर्तक	संपत्ति कार्ड की अनुपस्थिति के कारण विवाद	तकनीकी रूप से अद्यतन स्वामित्व विलेखों के माध्यम से अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा
4	संपत्ति कर के निर्धारण के लिए प्रवर्तक	कई राज्यों द्वारा संपत्ति कर संग्रह का निम्न स्तर	पंचायतों द्वारा संपत्ति करों के सुव्यवस्थित उद्ग्रहण से गांवों का सशक्तिकरण

संपत्ति कार्ड वितरण

राज्यों से संपत्ति कार्ड वितरण की कुछ झलकियां



26 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में संपत्ति कार्ड वितरण



26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड में संपत्ति कार्ड वितरण

- 24.04.2021 तक, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के लगभग 7500 गांवों में 7 लाख संपत्ति कार्ड / टाइटल डीड जारी किए गए हैं।

समर्थन : सरकार द्वारा



11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री



माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए



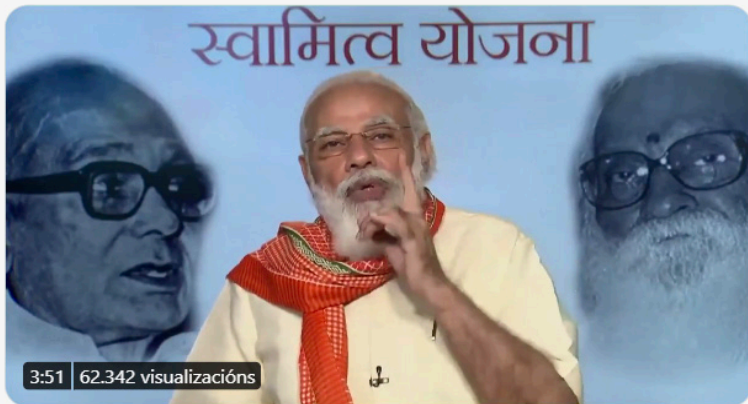
Narendra Modi @narendramodi · 11/10/2020

आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है।

स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है।

आज 6 राज्यों के लाखों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं।

#SampatiSeSampanta



Narendra Modi @narendramodi · 11/10/2020

चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने वाली बाराबंकी की रामरती जी को प्रॉपर्टी कार्ड से एक नया आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने बताया कि पूर्वजों की संपत्ति का कागज मिलने के बाद अब वे न केवल खुद को हर तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं, बल्कि अपना रोजगार भी बढ़ा सकेंगी। **#SampatiSeSampanta**



भारत के माननीय प्रधानमंत्री



Narendra Singh Tomar @nstomar · Feb 1

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

#AatmanirbharBharatKaBudget

#AatmanirbharBharat

की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं।

अब तक 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड किये गए हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

नरेन्द्र सिंह तोमर
भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वित्त एवं संसाधन विभाग, नई दिल्ली

f /narendrasinghtomar/p t /nstorar i /nstorar t /narendrasinghtomar

16

69

237



Narendra Singh Tomar @nstomar

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के 6 राज्यों के 763 गांवों के 1.32 लाख ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे...

कार्यक्रम से जुड़ने के लिए निम्न लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें : pmevents.ncog.gov.in

#SwamitvaYojana

स्वामित्व योजना

ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद कर रही है यह योजना...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

देश के 763 गांवों के 1.32 लाख ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे।
(दिल्ली- 22, गुजरात- 34, बिहार- 10, कर्नाटक- 44, उत्तरांचल- 40 और झारखंड- 22)

बीकानेर, दिल्ली 11 अक्टूबर 2020 | मात्र 11:00 बजे

कार्डों के जुड़ने के लिए निम्न लिंक पर जाएं रजिस्ट्रेशन करें
<https://pmevents.ncog.gov.in>

f /narendrasinghtomar/p t /nstorar i /nstorar

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वित्त एवं संसाधन विभाग, नई दिल्ली

12:39 PM · Oct 9, 2020 · Twitter Web App

77 Retweets 2 Quote Tweets 300 Likes

माननीय पंचायती राज मंत्री



Yogi Adityanath @myogiadityanath · Feb 12

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'स्वामित्व योजना' के अन्तर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का डिजिटल वितरण...



8:28 35.6K viewers

myogiadityanath www.yogiadityanath.in

Yogi Adityanath @myogiadityanath

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'स्वामित्व योजना' के अन्तर्गत ग्रामीण ...

pscpt.vt



334



1.6K



9.8K



उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री



Manohar Lal @mlkhattar · Jul 22, 2020

Lal Dora to end in Haryana with the SVAMITVA scheme that will resolve thousands of land possession disputes as well as boost revenue generation for the state.

Beginning of the end of Lal Dora: 12 villages to get land ownership proof

Mapping By Drones To Start Today

Shashank Singh @shashank1980

Gurgaon: For hundreds of villages in Haryana's Bhiwani and Sonapatna villages, who have been struggling to get back in pace to build houses on land they have no ownership proof. Wednesday will mark a new chapter as the state government begins an exercise to end the century-old Lal Dora system in the district.

As part of the state government's 'Swamitva' scheme, a 12-member team from Survey

12 TEAMS TO CARRY OUT THE SURVEY

WHAT IS LAL DORA?

The Lal Dora system came into being during the British regime in 1916. At the time, red lines were drawn on maps delineating village habitation from nearby agricultural land for revenue records.

How will villages be surveyed?

12 teams from the Survey of India will carry out the survey in 12 villages. As a result, the property owner was unable to get a plan from the banks. The system for the state includes: The more will be helping people in selling and purchasing

How will the process work?

The Swamitva scheme aims to end this system by surveying and demarcating inhabited land in red lines. It will create land records and issue property cards to villagers as proof of ownership.

The teams will mark properties with lime powder

Drones will be flown over them to get high-resolution images. These images will then be integrated with maps of the village to create land records.

who will get relief. Sube Singh Bhatta, former sarpanch of Wazirpur, said this will be a big reform as land will be registered in the name of the owner, bringing to an end to disputes on land possession and ownership. It will also help the government revenue as people will have to get their land registered as per the rules.

December 2022

Surveyor general of India Lt Gen Girish Kumar said 12 teams will mark properties with lime powder, identify drone over them to get high-resolution images. These images will then be integrated with maps. The result that flying aircraft or taking satellite images will not give us detailed results, so using drones was the best way to recreate

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री



Trivendra Singh Rawat ✓ @t... · 10/10/20 ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा कल दिनांक 11 अक्टूबर, पूर्वाह्न 11 बजे वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए pmevents.ncog.gov.in पंजीकृत करें।



भारत सरकार
Government of India



Ministry of Panchayati Raj
Government of India



my
GOV
मेरी सरकार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत
संपत्ति कार्ड का वितरण

11 अक्टूबर, 2020, सुबह 11:00 बजे



💬 24

↕️ 60

❤️ 285



उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री

समर्थन : मीडिया द्वारा

J Jansatta

500 ड्रोन से नापेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6 लाख गांव, जानें क्या है स्वामित्व स्कीम

SVAMITVA योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन ...



BL Business Line

SVAMITVA scheme will unleash productive forces in agriculture and non-farm rural activities

With digital records, banks can lend freely without much documentation. Formal lease markets and digitisation of personal records can lead to ...

M Mint

How PM Modi's 'Svmitva' scheme on property cards will benefit millions of rural property owners

SVAMITVA, a Central Sector Scheme of the Ministry of Panchayati Raj, which was launched by PM Modi on National Panchayati Raj Day, 24th ...

INIE New Indian Express

Aadhaar-like property cards for villagers under Svmitva

Karnataka is one among six states selected under this scheme. Each card will get a unique identity number similar to the Aadhaar card. Svmitva ...

Z Zee News

रातों-रात रंक से राजा बन गया रामभरोसे, जानिए कैसे जमीन ने उगले 21.14 लाख रुपए

रातों-रात रंक से राजा बन गया रामभरोसे, जानिए कैसे जमीन ने 'उगले' 21.14 लाख रुपए.

समर्थन : ग्राम पंचायतों द्वारा



स्वामित्व योजना को लेकर गांवों के निवासियों में काफी उत्साह व उत्सुकता है। चुना अंकन चरण के दौरान निवासियों ने अपनी भूमि की वास्तविकता को जाना है। यह योजना गाँव के निवासियों के बीच काफी चर्चा में रही है और कुछ लाभार्थियों ने होमस्टे के निर्माण के लिए बैंक ऋण भी लिया है। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से निवासी काफी खुश हैं।



श्रीमती सुमन गोदियाल,

ग्राम प्रधान, गोदा ग्राम, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड



योजना का लाभ मिलना गांव के लिए गर्व की बात है। चुना मार्किंग चरण के दौरान कोई विवाद नहीं था और लोगों को इस्तेमाल की जा रही तकनीक के स्तर और इसमें शामिल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर पूरा भरोसा है।



श्री विश्वनाथ कृष्ण मुजुमले,

पूर्व सरपंच, कोंधापुर गांव, पुणे, महाराष्ट्र



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार